

>

Title: Need to approve the proposals submitted by the Government of Madhya Pradesh for setting up de-addiction cum rehabilitation centres in the State and sanction Central grants for the purpose.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): भारत सरकार, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों के संचालन के 18 प्रस्ताव, नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र स्थापना के 17 प्रस्ताव, नशामुक्ति परामर्श सह प्रचार के दो प्रस्ताव तथा आर.आर.टी. सेंटर का एक प्रस्ताव केन्द्रीय अनुदान के लिए प्रेषित किए गए थे एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में नशामुक्ति केन्द्र संचालन के 8 प्रस्ताव एवं नवीन केन्द्र स्थापना के 7 प्रस्ताव केन्द्रीय अनुदान के लिए प्रेषित किए गए हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है।

अतएव सरकार से मांग है कि जनहित में यथाशीघ्र मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा भेजे गए उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की जाये।